दिल्ली, उ0प्र0, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एवं राजस्थान में प्रसारित।

गुरुकृपा दर्पण

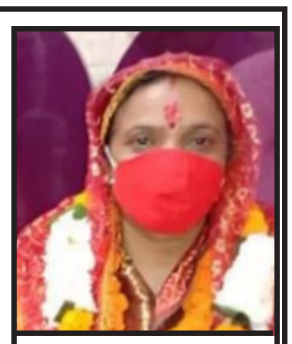

राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक

UTTHIN/2022/85670

डाक सं० UA/DO/DON/02/2024-2026

वर्ष : 04 | अंक : 06 | हरिद्वार | शनिवार, 8 फरवरी, 2025 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 4

आयुक्त गढ़वाल मंडल की अध्यक्षता में हुई वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक

देहरादून। आयुक्त गढ़वाल मंडल विनय शंकर पांडेय की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप कार्यालय ऋषिकेश में वर्ष 2025 की चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। जबकि सचिव लो.नि.वि. पंकज पाण्डेय ने वर्चुअल के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग किया। आयुक्त गढ़वाल ने चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित, सुविधाजनक बनाने हेतु सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध पूर्ण करने तथा यात्रा रूट की सड़कों को चाक चौबन्ध करने, पार्किंग क्षमता बढाने, पैदल मार्ग का सुधारीकरण, स्वास्थ्य सुविधा बेहतर बनाएं, हेली सर्विस व अन्य सुगम सुविधा पर अभी से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा 2025 की इस प्रथम यात्रा बैठक में बीते यात्रा वर्ष की कार्ययोजना के परिणामों की समीक्षा

आगामी श्री बद्रीनाथ, श्री केदारनाथ, श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री धाम तथा श्री हेमकुंट साहिब यात्रा की तैयारियों के विषय में मंथन हुआ। गढ़वाल आयुक्त ने अवगत कराया गया कि 04 मई 2025 से श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल रहे है साथ ही माह में अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेगे तथा 26 फरवरी 2025 को शिवरात्रि के दिन श्री केदारनाथ धाम के कपाट की तिथि एवं मुहर्त निकलेगा तदोपरान्त चारधाम यात्रा प्रारम्भ हो जायेगी। चारधाम यात्रा प्रारम्भ होने से पूर्व यात्रा सम्बन्धी धामो एवं यात्रा मार्गों मे अवस्थापना समबन्धी समस्त आवश्यक व्यवस्थाओं यथा पेयजल, चिकित्सा, परिवहन, खाद्यान, पुलिस, सफाई व्यवस्था. विद्युत व्यवस्था, दूरसंचार व्यवस्था, हेलीसर्विस व्यवस्था, आपदा कन्ट्रोल रूम को 24 घन्टे खुले रहने की सुचारू व्यवस्था रखने हेतु सम्बन्धित जिलो के जिलाधिकारियों एवं विभागो के प्रमुख अधिकारियों को अभी से तैयारियों करने हेतु निर्देशित किया गया, साथ ही गंगोत्री, यमुनोत्री, श्री केदारनाथ धाम, श्री बद्रीनाथ, धाम श्री हेमकुण्ड साहिब से आये प्रबन्धक, तीर्थपुरोहित समाज से आये विभिन्न मंदिर समितियो के अध्यक्ष एवं सचिव एवं रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्षो व पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावो पर यात्रियो के लिये पंजीकरण काउन्टर्स की संख्या ऋषिकेश एवं हरिद्वार के अतिरिक्त अन्य उपयुक्त स्थानो पर बढ़ायी गयी है। जिसके लिये पर्यटन विभाग को यात्रियो के पंजीकरण की सुगम व्यवस्था बनाने हेतु आनलाईन पंजीकरण को अतिशीघ्र शासन स्तर से निर्णय लेकर उसे अतिशीघ्र प्रारम्भ करने का आश्वासन दिया गया। बैठक में आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, जिलाधिकारी पौड़ी डा. आशीष चौहान, जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेंद्र सिंह, जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल मयूर दीक्षित, जिलाधिकारी उत्तरकाशी डा. मेहरबान सिंह बिष्ट, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग डा. सौरभ गहरवार, अपर आयुक्त गढ़वाल उत्तम सिंह चौहान, नगर आयुक्त ऋषिकेश शैलेंद्र सिंह नेगी, एसपी देहात देहरादून जया बलूनी, उप जिलाधिकारी ऋषिकेश स्मृता परमार आदि मौजूद रहे।

भतीजी के वैवाहिक कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड आगमन

जतिन शर्मा

देहरादून। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर 6 फरवरी को कैबिनेट मंत्री डा. प्रेमचंद अग्रवाल ने डोईवाला में जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का अभिवादन करते हुए मंत्री डा. अग्रवाल ने कहा कि उनके नेतृत्व में प्रयागराज में संचालित हो रहा महाकुंभ पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को फहरा रहा है। कहा कि उत्तराखंड से भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचे है। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित रहे।

गुरुकृपा दर्पण (राष्ट्रीय समाचार पत्र) को आवश्यकता है उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों के लिए ब्यूरो चीफ, कैमरा मैंन, संवादाताओं की। सम्पर्क करें – 9410731129, 9548880101

श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति की पुस्तिका एवं कैलेंडर का विमोचन

जतिन शर्मा

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के वर्ष 2025 के कैलेंडर एवं चारधाम यात्रा की जानकारी देने वाली पुस्तिका का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशित कैलेण्डर एवं देश की सात विभिन्न भाषाओं में तैयार पुस्तिका देश भर के श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिये प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि चारो धामों के तीर्थ स्थलों पर आधारित कैलेण्डर भी यात्रा को बढावा देने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रकाशित कैलेण्डर एवं पुस्तिका शीतकालीन यात्रा को भी बढावा देने में मददगार होंगे।

शीतकालीन यात्रा को राज्य की आर्थिकी को बढावा देने वाला प्रयास बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा की भांति शीतकालीन प्रवास स्थलों पर भी यात्रियों की सुविधाओं की आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई है। इस अवसर पर मुख्य मंत्री आवास के आला अधिकारी तथा बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल आदि मौजूद रहे।

मुजफ्फरनगर की गलियों में पुलिस का बड़ा सर्च ऑपरेशन!

रुड़की । खानपुर के गोवर्धनपुर में पुलिसकर्मियों पर पथराव करने वाले आरोपियों की तलाश तेज हो गई है। खानपुर पुलिस की टीम ने मुजफ्फरनगर के कई गांवों में छापेमारी की, लेकिन कोई आरोपी पकड़ में नहीं आया। स्थानीय पुलिस के सहयोग से हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दबिश दी, लेकिन सभी फरार मिले। अब पुलिस आरोपियों के ठिकानों की नई सूची तैयार कर रही है और जल्द ही फिर से बड़ी कार्रवाई की जाएगी। 31 जनवरी को लक्सर में ब्राह्मण समाज की पंचायत बुलाई गई थी। पुलिस ने पंचायत में आने वाले कुछ लोगों को आगे बढ़ने से रोका, जिस पर कुछ उपद्रवियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। इस घटना में सिपाही सुमित सिंह, महावीर सिंह और होमगार्ड नीटू कुमार घायल हो गए थे।

सम्पादकीय

लुभावनें वायदें

सम्पादक – देवेन्द्र जौहरी

जनता को सुविधाए दिलाना जनप्रतिनिधियों का कार्य है इस कार्य को वह जनसेवक के रूप में करे तो अच्छा। लेकिन वर्तमान में ये जनप्रतिनिधि जनता चुनावी वायदों से लुभा रहे है। सड़क से लेकर सीवर तक, पर्यावरण से लेकर विकास तक दिल्ली के बुनियादी मुद्दे की जगह मुफ्त की सुविधाओं की होड़ ने दिल्ली के चुनाव को जिन त्रासद दिशाओं में धकेला है, वह न केवल दिल्ली बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के लिये एक चिन्ता का बड़ा सबब बन रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी –तीनों दलों ने अपने-अपने घोषणापत्र जारी किए हैं लेकिन उसमें दिल्ली से जुड़े जरूरी एवं बुनियादी मुद्दों के स्थान पर नगद एवं मुफ्त की सुविधाओं के ही अंबार लगे हैं। दिल्ली चुनाव में अधिकांश बहस तरह-तरह की मुफ्त सुविधाओं की अप्रासंगिक और अवांछित विषयों पर केंद्रित है। जल्दी ही दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे देश की राजधानी के चुनाव में इससे बेहतर की उम्मीद थी। चूंकि जरूरी मुद्दें नहीं उठ रहे हैं इसलिए भाषा भी निम्नस्तरीय बनी हुई है, दोषारोपण एवं छिद्रान्वेषण ही हो रहा है। राजनीतिक दलों द्वारा अप्रासंगिक मुद्दों पर बात करने की एक खास वजह चुनावों की प्रक्रिया में मुफ्त की सुविधाएं एवं नगद राशि का बढ़ता आकर्षण है।

महाकुंभ 2025 प्रयागराज में आयोजित श्रीरामनाम अराधना मंडल सेवाशिविर : आचार्य स्वामी दिव्यांश

जतिन शर्मा

हरिद्वार/प्रयागराज। परमपूज्य श्रीमद्जगदगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्यामनारायणाचार्य जी महाराज (हरिद्वार एवं अयोध्या पीठाधीश्वर) आचार्य बेला हरिद्वार के पावन सानिध्य में युवराज स्वामी श्री दामोदराचार्य जगदगुरु रामानुजस्वामी दिव्यांश जी महाराज, इंडिया टेंपल हरिद्वार और युवराज स्वामी श्री मदनमोहनाचार्य जी महाराज श्री मधुसूदन वैकुंठ धाम आश्रम श्री अयोध्या धाम द्वारा सेक्टर 16 अनंत माधव चौराहा शंकराचार्य मार्ग प्रयागराज में महाकुंभ 2025 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ आयोजित किया जा रहा है। कथा प्रवक्ता परमपूज्य स्वामी रंगनाथाचार्य जी महाराज अवंतिका पीठाधीश्वर के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रीरामनाम आराधना मंडल सेवा शिविर में कथा श्रवण किया जा रहा है। परमपूज्य श्रीमद्जगदगुरु रामानुजाचार्य श्री स्वामी श्यामनारायणाचार्य जी महाराज (हरिद्वार एवं अयोध्या पीठाधीश्वर) आचार्य बेला हरिद्वार के पावन सानिध्य में अन्य अन्य राज्यों से आये भक्तो की व्यवस्था श्रीरामनाम आराधना मंडल सेवा शिविर में सेवा की जा रही है जिसमें कथा श्रवण करने वाले भक्तों के लिए रहने खाने की सभी व्यवस्थाएं आश्रम द्वारा संचालित है।

डीएम ने की त्वरित जनसुनवाई, कई समस्याओं का समाधान

हरिद्वार। जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हरिद्वार तहसील सभागर में तहसील दिवस सम्पन्न हुआ। जिसमें फरियादियों द्वारा कुल 19 समस्याएं एवं मांग दर्ज कराई गई, जिसमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराने के लिए आदेशित किया गया। तहसील दिवस में मुख्यत: शिकायतें पैमाईश, कब्जा तथा जल निकासी आदि से सम्बन्धित थीं। अनिल गुप्ता निवासी शांतिपुरम कॉलोनी ने छोटी पुलिया की जर्जर हालत और अवैध कब्जा से मुक्त करने के संबंध में शिकायत पर जिलाधिकारी ने नगर आयुक्त नगर निगम ओर ईई सिंचाई विभाग को जॉच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए, गुलशन कक्कड़ द्वारा सुभाष घाट पर तख्त पर कब्जे को लेकर शिकायत की जिस पर जिलाधिकारी एसएचओ कोतवाली हरिद्वार को जांच करने के निर्देश दिए, जगपाल सिंह पुत्र छोटा निवासी हरदेवपुर सहदेवपुर ने पड़ोसियों द्वारा खेत की डोल पर अवैध कब्जा कर पेड़ लगा दिए के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया जिस पर जिलाधिकारी द्वारा उपजिलाधिकारी हरिद्वार को जांच कर रिपोर्ट देने का निर्देशित किया, नौमान पुत्र इकबाल निवासी नीलखुदाना ज्वालापुर ने जानमाल की रक्षा को लेकर प्रार्थना पत्र के संबंध में जिलाधिकारी ने सीओ ज्वालापुर को वाद की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर करवाई करने निर्देश दिए, सोमराज पुत्र मणिराम निवासी ग्राम हजारा ग्रन्ट ने भूमि पैमाईश के लिए प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार हरिद्वार को जॉच करने के निर्देश दिए, सुरेंद्र पुत्र मेहरबान निवासी हाइवे ग्रीन ज्वालापुर ने श्रीराम एनक्लेव ग्राम ज्वालापुर में पड़ोसियों द्वार जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार हरिद्वार को वाद जांचकर कार्यवाही के निर्देश दिए, ग्राम प्रधान शशिपाल सिंह ने ग्राम पंचायत पीलीपढाव में विभागीय संपति की सुरक्षा ओर मीठीबेरी गांव से लालढांग गांव तक सड़क बनवाने के प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार हरिद्वार जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए साथ ही ईई पीडब्लूड़ी को जांच कर निस्ताकरण के निर्देश दिए, लोकेश मेंहदीरत्ता निवासी चंद्राचार्य अपार्टमेंट कनखल ने ग्राम देवपुर मुरहकम तहसील ने पड़ोसियों द्वारा अवैध कब्जे को लेकर शिकायत की जिस पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार हरिद्वार को जांच करने के निर्देश दिए, खालिद पुत्र इब्राहिम ग्राम मुस्तफाबाद ने ग्राम पंचायत मुसफाबाद मैं जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी के लिए खुदाई की जा रही है ठेकेदार द्वारा बाकी जगह रोड के बीच में खुदाई की जा रही है और जबकि मेरे मकान की जड़ में खुदाई की जा रही है इस को लेकर शिकायत की जिसपर जिलाधिकारी ने ईई जलस्थान को परीक्षण कर निस्तारण करने के निर्देश दिए।

हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया

हरिद्वार। गाडोवाली और मिस्सरपुर की आवासीय कालोनी में बीती रात हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों के झुण्ड सुबह तक आसपास के खेतों में ही टहलते रहे। किसानों ने वन विभाग पर हाथियों को रोकने में लापरवाही का आरोप लगाया। गाडोवाली और मिस्सरपुर के खेतों में हाथियों ने गन्ने और गेहूं की फसल को चट कर दिया।

हरिद्वार में विकास की रफ्तार, लेकिन विपक्ष बना रोड़ा : स्वामी यतीश्वरानंद

हरिद्वार । हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने सड़क निर्माण, श्मशान घाट, चाहरदीवारी और प्रवेश द्वार जैसी आधारभूत संरचनाओं पर काम शुरू किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां सरकार विकास की गंगा बहाने में जुटी है, वहीं विपक्ष उसमें रोड़े अटका रहा है। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अपनी समस्याएं बेहिचक बताएं, ताकि उनके समाधान के लिए ठोस कदम उठाए जा सकें। स्वामी यतीश्वरानंद ने बताया कि इन सभी विकास कार्यों पर 1 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। इन योजनाओं में झाबरी में प्रवेश द्वार, अंबूवाला में श्मशान घाट, सुकरासा में सड़क मार्ग, डांडी में द्वार और श्मशान घाट, इब्राहिमपुर में सड़क व चाहरदीवारी और एक्कड़ में प्रवेश द्वार का निर्माण शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने शाहपुर शीतलाखेड़ा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया।

देवेन्द्र जौहरी
सहसम्पादक
जतिन शर्मा
सहसम्पादक
विक्रान्त शर्मा
कानूनी सलाहकार
जसमहिन्द्र सिंह एडवोकेट

आखिर चुनावी रेवड़ी को परिभाषित करना इतना मुश्किल क्यों है?

कमलेश पांडेय ।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पूरे दिल्ली में %रेवड़ी पर चर्चा% अभियान की शुरूआत कर दी थी। इस मौके पर उन्होंने दो टूक कहा था कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक़ भी जनता का ही है।दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा करते वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि %चुनावी रेवड़ी% क्या है, इसे परिभाषित करना मुश्किल है। चूंकि इस मुद्दे पर आयोग के हाथ बंधे हुए हैं। इसलिए, कानूनी उत्तर ढूंढे जाएं। हालांकि, उनकी इस साफगोई से हमारी संसद और हमारे संविधान के संरक्षक सुप्रीम कोर्ट, दोनों की जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। वह यह कि वो जल्द से जल्द इस मसले पर व्याप्त कानूनी असमंजस को दूर करने के लिए एक नेक पहल करें। वहीं, अब तक ऐसा नहीं होना निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया पर एक गम्भीर सवालिया निशान छोड़ जाता है। क्योंकि जब इस मसले पर स्पष्ट नियमन होंगे तो इसका उल्लंघन करने वाले राजनीतिक दलों व उनके नेताओं को कानून के कठघरे में खड़ा किया जा सकेगा। हालांकि, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की बात से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आजादी और गणतंत्र बनने के इतने दशकों बाद भी हमारे सत्ता पक्ष या विपक्ष ने कभी इस मुद्दे पर स्पष्ट नियमन बनाने की पहल ही नहीं की, ताकि दुविधाजनक कानूनी परिस्थितियों से चुनावी लाभ उठाते रहा जाए। जबकि, मीडिया में इस बारे में जब-तब बहस होती रहती है, और सर्वोच्च न्यायालय में भी इस बारे में कुछ जनहित दायर है, जिस पर दो टूक निर्णय की प्रतीक्षा देशवासियों को है। लेकिन वर्ष 2018 से अब तक इस पर स्पष्ट निर्णय नहीं हो पाया है। यह गम्भीर बात है, क्योंकि इससे इस अहम मसले पर राजनेताओं और सम्बन्धित पेशेवरों द्वारा जितने मुंह, उतनी बातें की जा रही हैं जिससे मतदाता भी असमंजस में हैं। इसके उलट जिन्हें फ्रीबीज यानी मुफ्त की चुनावी रेवड़ी का लाभ मिल रहा है, उनकी तो बल्ले बल्ले है। वहीं, जिन करदाताओं की जेबें तरह-तरह के टैक्स के माध्यम से हर रोज काटी जा रही हैं और सरकार प्रदत्त जनसुविधा भी नदारत या नाकाफी दिख रहीं हैं, उनके दिलोदिमाग में इस सियासी प्रवृत्ति को लेकर अनेक सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी गत दिनों फ्रीबीज मामले पर सख्त टिप्पणी की और कहा कि राज्यों के पास उन लोगों को 'मुफ्त सौगात' देने के लिए पर्याप्त धन है, जो कोई काम नहीं करते। लेकिन जजों की सैलरी-पेंशन देने के लिए नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राज्य के पास मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जजों की सैलरी-पेंशन देने के लिए नहीं है। राज्य सरकारों के पास उन लोगों के लिए पूरा पैसा है, जो कुछ नहीं करते; लेकिन जब जजों की सैलरी की बात आती है तो वे वित्तीय संकट का बहाना बनाते हैं। बता दें कि जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह मौखिक टिप्पणी उस समय की, जब अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ से जुड़ी एक याचिका के निपटारे के क्रम में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने दलील दी कि सरकार को न्यायिक अधिकारियों के वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों पर निर्णय लेते समय वित्तीय बाधाओं पर विचार करना होगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि, राज्य के पास उन लोगों के लिए पैसा है जो कोई काम नहीं करते। चुनाव आते हैं, आप लाडली बहना और अन्य नयी योजनाएं घोषित करते हैं, जिसके तहत आप निश्चित राशि का भुगतान करते हैं। दिल्ली में अब आए दिन कोई न कोई पार्टी घोषणा कर रही है कि वे सत्ता में आने पर 2,500 रुपये देंगे। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पेंशन के संबंध में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ की ओर से 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। जबकि, अटार्नी जरनल आर वेंकटरमणि ने कहा कि वित्तीय बोझ की वास्तविक चिंताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि, यह 'दयनीय' है कि उच्च न्यायालय के कुछ सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को 10,000 रुपये से 15,000 रुपये के बीच पेंशन मिल रही है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है, जब दिल्ली चुनाव में फ्रीबीज की बहार है। आम आदमी पार्टी ने वादा किया है कि उसकी सरकार बनी तो महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मिलेंगे। जबकि कांग्रेस 2500 रुपए देने की बात कह रही है। वहीं, भाजपा भी इसी तरह का ऐलान जल्द करने वाली है। उधर, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही पूरे दिल्ली में %रेवड़ी पर चर्चा% अभियान की शुरूआत कर दी थी। इस मौके पर उन्होंने दो टूक कहा था कि जनता का पैसा, जनता की रेवड़ी, तो उस पर हक़ भी जनता का ही है। केजरीवाल ने कहा कि, %पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि केजरीवाल मुफ़्त की रेवड़ी दे रहे हैं और इसे बंद किया जाना चाहिए। जबकि केजरीवाल खुलेआम कह रहा है कि हम ये रेवड़ी दे रहे हैं। अब दिल्ली के लोगों को तय करना है कि उन्हें ये रेवड़ी चाहिए या नहीं। उन्होंने आगे चेताया कि, अगर बीजेपी जीतती है तो वे ये योजनाएं बंद कर देगी। क्योंकि बीजेपी ने अपने और अपने गठबंधन द्वारा शासित राज्यों में ये रेवड़ियां लागू नहीं की हैं। हालांकि उसकी कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने दो टूक कहा कि, ये मुफ़्त की रेवड़ी नहीं हैं बल्कि ये करदाताओं के पैसे से लागू की गई योजनाएं हैं। वहीं, चुनाव आयोग ने भी इस मुद्दे पर कहा था कि, जिसे आप सामान्य भाषा में %फ्रीबीज़% यानी मुफ़्त की चीज़ें कह रहे हैं, वे महामारी जैसे दौर में लोगों की जान बचा सकती हैं। हो सकता है एक वर्ग के लिए जो अतार्किक हो वो दूसरे वर्ग के लिए ज़रूरी हो। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक पार्टियों और मुफ़्त में सुविधाएं दिए जाने का ज़िक्र करते हुए एक बार कहा था कि, इस तरह के वादे करके वोटरों को लुभाना राष्ट्र निर्माण नहीं, बल्कि राष्ट्र को पीछे धकेलने की कोशिश है। अगर राजनीति में ही स्वार्थ होगा तो कोई भी आकर पेट्रोल-डीज़ल भी मुफ़्त देने की घोषणा कर सकता है। ऐसे क़दम हमारे बच्चों से उनका हक़ छीनेंगे। देश को आत्मनिर्भर बनने से रोकेंगे। ऐसी स्वार्थभरी नीतियों से देश के ईमानदार करदाता का बोझ भी बढ़ता ही जाएगा। ये नीति नहीं %अनीति% है। ये राष्ट्रहित नहीं, ये राष्ट्र का अहित है। एक बार पीएम मोदी ने बुंदेलखंड-एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करते हुए उत्तर प्रदेश के जालौन में तो यहां तक कह दिया था कि, आजकल हमारे देश में मुफ़्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ़्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें ख़रीद लेंगे। हमें मिलकर रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। वहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि, कहा जा रहा है कि अगर सरकारें जनता को फ्री में सुविधाएं देंगी तो सरकारें कंगाल हो जाएंगी। देश के लिए बहुत आफ़त पैदा हो जाएगी। इन सारी फ्री की सुविधाओं को बंद किया जाए। इससे मन में एक शक पैदा होता है कि कहीं केंद्र सरकार की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं हो गयी है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन सारी चीजों को बंद करने, वापस लेने या इनका विरोध करने की स्थिति आ गई। इससे दो कदम आगे बढ़कर उन्होंने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने करोड़पति उद्योगपतियों के दस लाख करोड़ रुपए के कर्ज़ माफ़ किए थे। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा था कि, जब 2014 में केंद्र सरकार का बीस लाख करोड़ का बजट होता था। और आज केंद्र सरकार का बजट लगभग चालीस लाख करोड़ का है तो ये सारा पैसा जा कहां रहा है। इन्होंने बहुत अमीर लोग जो अरबपति हैं, उनके दस लाख करोड़ रुपये के कर्ज़े माफ कर दिए। अगर ये हज़ारों लाखों करोड़ों रुपये के कर्ज़े माफ़ नहीं किए जाते तो इन्हें खाने-पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि एक बार कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल का जवाब ट्वीट किया था। जिसके अनुसार 2017 से लेकर 2022 के बीच बैंकों ने क़रीब 10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज़ माफ़ किए हैं। तब उनका कहना था कि सरकार मध्यवर्ग के करदाताओं को लूट रही है। लिहाजा इसी का ज़िक्र अरविंद केजरीवाल ने भी किया था, जो सही है। वहीं, चुनाव अभियानों में राजनीतिक पार्टियों के मुफ़्त चीज़ें और पैसे देने के वादों से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसे %एक गंभीर मुद्दा% बताया है। वर्ष 2022 में ही एक याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन चीफ़ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी की बेंच ने कहा था कि- ये एक गंभीर मुद्दा है। जिन्हें ये मिल रहा है वो ज़रूरतमंद हैं और हम वेलफ़ेयर स्टेट हैं। कुछ टैक्सपेयर कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल विकास के लिए किया जाए। इसलिए ये गंभीर मुद्दा है। अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान और वेलफ़ेयर में बैलेंस की ज़रूरत है। दोनों ही पक्षों को सुना जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि इस बाबत जनहित याचिका दायर करने वाले बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने गुज़ारिश की है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों के चुनावी घोषणापत्र को नियंत्रित करने और उनके वादों के लिए उन्हें ज़िम्मेदार ठहराने से जुड़ा क़ानून लाए और बिना सोच समझकर अतार्किक वादे करने वाली पार्टियों को बैन करे। उनका कहना है कि मुफ़्त चीज़ों की घोषणा करते वक़्त राजनीतिक पार्टियां सरकार पर पड़ रहे कर्ज़ के बोझ का ध्यान रखें और बताएं कि इसके लिए पैसा किसकी जेब से आ रहा है। इस बारे में अश्विनी उपाध्याय ने बताया था कि, हमने कोर्ट से यही कहा है कि इस समय केंद्र और राज्य सरकारों पर 150 लाख करोड़ रुपये का कर्ज़ हो चुका है। अगर इसे नहीं रोका गया तो आने वाले समय में स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। हमें न विश्व बैंक, न अमेरिका, न जापान कर्ज़ देगा। स्थिति नियंत्रण के बाहर हो जाएगी। केंद्र सरकार ने भी हमारी जनहित याचिका का समर्थन किया है और कहा है कि जन कल्याणकारी योजनाएं तो चलनी चाहिए लेकिन मुफ़्तखोरी की योजनाएं बंद होनी चाहिए। हमने अपनी ओर से सात सदस्यों की एक समिति का प्रस्ताव दिया है। यह समिति बताए कि मुफ़्तखोरी को कैसे रोका जाए और राज्यों पर जो कर्ज़ बढ़ रहा है, उसे कैसे कम किया जाए। यूँ तो भारत में इससे पहले भी सब्सिडी के मुद्दे पर विचार-विमर्श होता रहा है। सब्सिडी के औचित्य आदि पर गंभीर चर्चाएं हुई हैं। लेकिन इस मुद्दे पर इस तरह राजनीतिक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप ने नए सुलगते हुए सवाल खड़े किए हैं। वह यह कि क्या मुफ़्त में चीजें या सेवाएं देना उचित है? क्योंकि राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ़्त में चीज़ें या सुविधाएं देने का वादा हमेशा से करती रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये किया जाना उचित है? इस विषय पर राजनीतिक मामलों के जानकार बताते हैं कि जब आप वोट मांगने जाते हैं तो इस तरह की बातें कहनी होती हैं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि सामान्य रूप से ये कहना कि हम सबका ध्यान रखेंगे और स्पेसिफिक रूप से कहना जैसे %15 लाख आएंगे और हम सबको दे देंगे।% उन्हें लगता है कि इस तरह स्पेसिफिक वादे करना ग़लत होता है। ये कहना भी ग़लत है कि हम जब आएंगे तो बिजली के बिल में दो या तीन रुपये माफ़ कर देंगे या बिलकुल ही ख़त्म कर देंगे। दरअसल, ये प्रवृत्ति किसी एक दल की नहीं है, बल्कि सभी दलों की होती है लेकिन ये प्रवृत्ति रुकनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी नियम कानून होने चाहिए कि उसे किस तरह होना चाहिए। इसकी जवाबदेही भी होनी चाहिए। लेकिन क्या जन कल्याणकारी योजनाओं और हाल ही में सामने आए टर्म %मुफ़्त की रेवड़ी% को एक तरह देखा जा सकता है? इस सवाल पर जानकार बताते हैं कि एक ऐसा समाज जहां आर्थिक और सामाजिक समेत तमाम तरह की विषमताएं हैं। वहां सभी के लिए एक जैसा कदम नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में वंचितों और शोषितों का कल्याण करना हर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में अगर आपका काम बहुसंख्यक समाज को लाभांवित नहीं करेगा तो आप चुनकर नहीं आ सकते। ऐसे में ये कहा जाए है कि हमारी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएगी। यहां तक तो ठीक है। लेकिन धीरे-धीरे ये होने लगा है कि जनता से वादे करो और फिर भूल जाओ। ऐसे में पहले जो एक फुंसी थी, उसने अब कैंसर का रूप ले लिया है। इस प्रवृत्ति का नतीजा ये हुआ कि कहा जाने लगा कि हम फ्री बिजली देंगे। पानी देंगे। गैस देंगे, आदि आदि। बताइए कि कोई भी सरकार फ्री बिजली कैसे दे सकती है। आख़िरकार पैसा टैक्सपेयर का है। और फ्री बिजली सबको क्यों मिलनी चाहिए...जो लोग बिजली ख़रीद सकते हैं, उन्हें फ्री में क्यों मिलनी चाहिए।

लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट में गूंजा गायत्री महामंत्र

जतिन शर्मा

हरिद्वार। लंदन (इंग्लैण्ड) के हाऊस ऑफ पार्लियामेंट में गायत्री महामंत्र का उच्चारण होते ही अखिल विश्व गायत्री परिवार में हर्षोल्लास की लहर महसूस हुई, यह पल अखिल विश्व गायत्री परिवार के सदस्यों एवं भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने का ऐतिहासिक पल बना। वर्ष 2026 गायत्री परिवार की संस्थापिका माता भगवती देवी शर्मा की जन्म शताब्दी वर्ष है और सिद्ध अखण्ड दीपक का भी सौ वर्ष पूरा हो रहा है। इस स्वर्णिम अवसर को अखिल विश्व गायत्री परिवार वृहद् स्तर पर मनाने जा रहा है। इस आयोजन हेतु अग्रिम पंक्ति में कार्य कर रहे देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉ चिन्मय पण्ड्या इन दिनों एक विशेष आयोजन हेतु लंदन (इंग्लैण्ड) के हाऊस ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे और वहाँ उपस्थित मंत्रियों, सदस्यों एवं अधिकारियों को इस स्वर्णिम अवसर पर गायत्री महामंत्र और अखिल विश्व गायत्री परिवार की गतिविधियों पर विस्तृत जानकारी साझा की। वैदिक परंपरानुसार देवस्थापना के चित्र की स्थापना कर पूजा अर्चना की और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना किया। यह पहला मौका है- किसी यूरोपीय देशों की उच्च सदनों में गायत्री परिवार द्वारा देवस्थापना हुई और सर्वे भवन्तु सुखिन: के भाव से प्रार्थना की गयी। आयोजन के दौरान उपस्थित समस्त मंत्रीगण, संसद सदस्य एवं अधिकारीगण पीतवस्त्र धारण किये और गायत्री परिवार के आयोजन में श्रद्धा भाव से शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि यूरोपीय देशों में किसी समाजसेवी संस्था द्वारा यह पहला कार्यक्रम है। युवा आइकॉन डॉ चिन्मय पण्ड्या के नेतृत्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार न केवल भारत में वरन् विश्व के अस्सी से अधिक देशों में विस्तार हो रहा है। हाऊस ऑफ पार्लियामेंट, वेस्टमिंस्टर (लंदन) में आयोजित इस सभा को संबोधित करते हुए युवा आइकॉन डॉ पण्ड्या ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, जहाँ गायत्री महामंत्र का गुंजायमान हुआ और शान्तिपाठ का भी सस्वर उच्चारण हुआ। गायत्री परिवार के लिए भी अलौकिक क्षण है। उन्होनें कहा कि यह एक ऐसा स्थान है, जहाँ विश्व के लिए अनेक उपक्रमों का जन्म हुआ है। इस दौरान इंग्लैण्ड के मंत्री, संसद सदस्यों आदि को युगऋषि पूज्य गुरुदेव द्वारा संपादित आर्ष साहित्य आदि भेंटकर सम्मानित किया। इस अवसर पर इंग्लैण्ड के कई मंत्री, सांसद सहित एफआईएल के निदेशक लार्ड रावल, बिशप लूसा, बिशप स्नाइडर, पार्लियामेंट के अनेक अधिकारीगण मौजूद रहे।

यूसीसी लागू होने से महिलाओं को मिलेगा बराबरी का अधिकार : शायरा बानो

जतिन शर्मा

देहरादून/काशीपुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में काशीपुर की शायरा बानो ने मुलाकात कर प्रदेश में यूसीसी लागू करने पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए शायरा बानो ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्य में महिलाओं को बराबरी के अधिकार मिलेंगे। उन्होंने कहा यूसीसी लागू होने से राज्य में महिलाओं में खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा यूसीसी समाज में समानता स्थापित करेगा, जिससे देश और राज्य को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी।

कण्वाश्रम महोत्सव के अंतिम दिन चलाया सफाई अभियान

कोटद्वार। कण्वाश्रम महोत्सव के अंतिम दिन कण्वाश्रम क्षेत्र में वृहद स्वच्छता अभियान चलाकर, स्वच्छता का संदेश दिया गया। इस दौरान क्षेत्र से 1 कुंतल से अधिक कचरा एकत्र किया गया। कण्वाश्रम में आयोजित तीन दिवसीय कण्वाश्रम महोत्सव के अंतिम दिन स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान मेला आयोजन समिति के सदस्यों, राष्ट्रीय स्वयंसेवा योजना के स्वयंसेवियों, स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने मेला आयोजनस्थल, मालन नदी एवं कण्वाश्रम मंदिर में साफ-सफाई की

एम्स ऋषिकेश में अब उच्च तकनीकी वाले एंडोवेस्कुलर न्यूरोइंटरवेंशन शुरू

जतिन शर्मा

ऋषिकेश। अस्पताल में मरीजों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को संस्थान प्रतिबद्ध है। जिसके तहत संस्थागत स्तर पर लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को विस्तार दिया जा रहा है। जिससे उत्तराखंड व समीपवर्ती राज्यों के मरीजों को गंभीर श्रेणी के इलाज के लिए अन्यत्र परेशान नहीं होना पड़े- प्रोफेसर (डॉ.) मीनू सिंह, कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ, एम्स ऋषिकेश। एम्स दिल्ली व पीजीआइ चंडीगढ़ की तरह इस संस्थान में भी ब्रेन व स्पाइन की खून की नसों से संबंधित बीमारियों का बिना चीरफाड़ के उपचार एम्स की कार्यकारी निदेशक एवं सीईओ प्रोफेसर (डॉ.) मीनू सिंह के निर्देशन में संस्थान के इंटरवेंशन रेडियोलॉजी विभाग में उच्च तकनीकी वाले न्यूरो इंटरवेंशन जैसे कैरोटिड स्टेंटिंग (खून की नस में सिकुड़न) ए.वी.एम व ए.वी.एफ (खून की नसों का गुच्छा) , स्ट्रोक (लकवा) एन्यूरिजम (खून की नसों का गुब्बारा व नसों का फटना) समेत कई अन्य तरह की बीमारियों का बिना किसी चीरफाड़ के इलाज उपलब्ध है। बताया गया है कि यह उपचार एम्स अस्पताल में मरीजों को बीते आठ महीने से आयुष्मान भारत योजना के तहत निशुल्क दिया जा रहा है। संस्थान में यह कार्य दिल्ली एम्स से प्रशिक्षित एवं वर्तमान में एम्स ऋषिकेश के इंटरवेंशन रेडियोलॉजी विभाग (भूतल बी- ब्लॉक) में कार्यरत सहायक आचार्य डॉ. बी.डी. चारण (डी.एम. न्यूरोइंटरवेंशन) द्वारा मरीजों में इस तरह की बीमारियों के उपचार को अंजाम दिया जा रहा है। विषय विशेषज्ञ डॉ. बी.डी. चारण ने बताया कि विभाग की

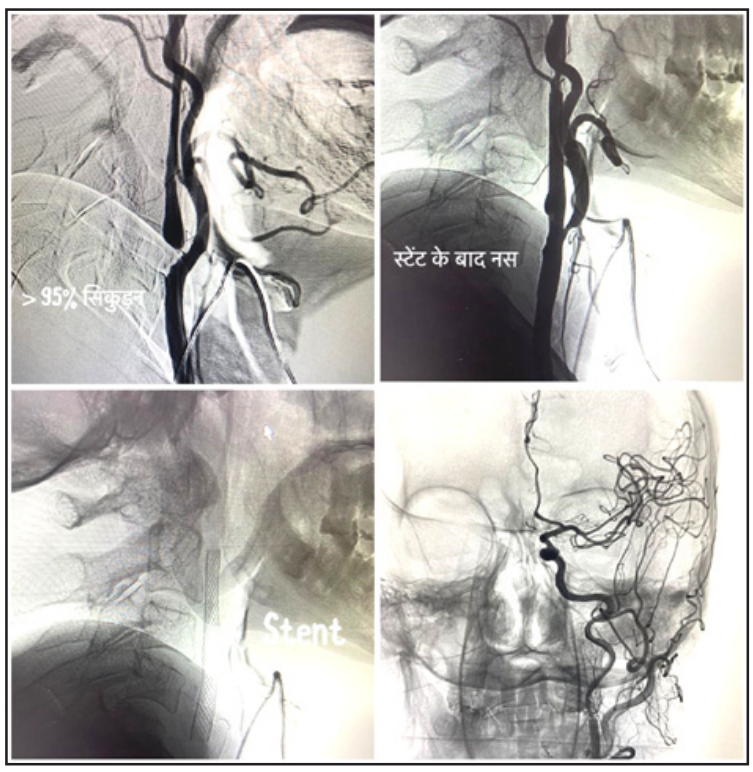

डीएसए लैब (पांचवीं मंजिल) में उपचार की यह प्रक्रिया एनेस्थीसिया विभाग के सहयोग से संपन्न की जाती है, जिसमें अन्य विभागों जैसे जेरियाट्रिक मेडिसिन, ईएनटी, नेत्र विभाग, न्यूरोसाइंस व मेडिसिन आदि का भी योगदान रहता है। डॉ. चारण के मुताबिक इस विधि के तहत जांघ की खून की नस में 2 एमएम का पाइप डालकर ब्रेन तक पहुंच बनाई जाती है, उसके बाद बीमारी का बिना चीरफाड़ किए इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि चूंकि इस उपचार में चीरफाड़ नहीं किया जाता है, लिहाजा मरीज को अस्पताल अथवा आईसीयू में निहायत कम समय तक ही रुकना पड़ता है और मरीज की जल्दी छुट्टी कर दी जाती है।

क्या कहते हैं विभागीय चिकित्सक

रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष प्रो. अंजुम सय्यद, डॉ. पंकज शर्मा, डॉ. उदित चौहान ने बताया कि हमारा विभाग ब्रेन व पूरे शरीर की खून की नसों से संबंधित बीमारियों का गुणवत्तापरक इलाज के लिए प्रतिबद्ध है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक
देवेन्द्र जौहरी द्वारा
साप्ताहिक समाचार पत्र
''गुरुकृपा दर्पण'' को
रूद्र प्रिंटिग प्रेस, ई-34,
ओल्ड इड्रस्ट्रियल एरिया, हरिद्वार
(उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं
एस-3, अशोक विहार कालोनी,
कनखल, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)
से प्रकाशित।
सम्पादक: **देवेन्द्र जौहरी**
मो.- **9997331129**
E-mail :
gurukripadarpan@gmail.com